रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 1970 (ज्येष्ठ 9, 1892)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 1970 (JYAISTHA 9, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 अप्रैल 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th April 1970:—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
52	No. WB-21(7)/69, dated 28-3-70	Min, of Labour Employment and Reh.	Resolution to set up a Central Wage Board for the port dock workers at the major ports.
53	No. 48-ITC (PN)/70, dt. 31-3-70.	Min. of Foreign Trade Import Trade Control.	Import Policy for the year April 1970—March 1971.
54	No. 47-ITC(PN)/70, dt. 31-3-70.	Min. of Foreign Trade.	Import policy for Registered Exporters—Procedure for certification of exports.
55	No. 1/70 dt. 31-3-70.	Do.	Import Trade Control—Open general licence No. LXXXVIII.
56	No. 49-ITC (PN)/70, dt. 31-3-70.	Do.	Import Policy for the year April 1970—March 1971.
57	No. F. 4 (5)-W&M/70, dt 2-4-70.	Min. of Finance	The issues of 4½% Banks (Acquisition and Transfer) compensation Bonds 1979 and 5½% Banks (Acquisition and Transfer) Compensation Bonds 1999 for payment of compensation.
	सं० एफ० 4(5)—डब्ल्यू० एण्ड एम०/70, दिनांक 2-4-70।	वित्त मंत्रालय	क्षतिपूर्ति की अदायगी करने के लिए साढ़े चार प्रतिशत ब्याज वाले बैंक (अधिग्रहण और अन्तरण) क्षतिपूर्ति बाण्ड 1979 और साढ़े पांच प्रतिशत वाले बैंक (अभिग्रहण और अन्तरण) क्षतिपूर्ति बाण्ड 1999 जारी करना।
58	No. 50-ITC (PN)/70, dt.4-4-70.	Min. of Foreign Trade	Licensing conditions for seventh kipping loan K.K./India Mixed Imports Loan 1969.
59	No. 51-ITC(PN)/70, dt. 7-4-70.	Do.	Import policy for News print for the year April 70—March/71 (S. No. 44/V).
60	No. RS 1/1/70-L, dt. 8-4-70.	Rajya Sabha Sectt.	The President prorogues the Rajya Sabha on 7th April/70.
	स० आर० एस० 1/1/70-एल०, दिनाक 8-4-70।	राज्य सभा सचिवालय	राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा का सत्रावसान करना।

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
61	No. 52-ITC(PN)/70, dt. 8-4-70.	Min. of Foreign Trade	Import Policy for the year April, 1970—March 1971.
62	No. RS 1/2/70-L, dt. 9-4-70.	Rajya Sabha Sectt.	The President summons the Rajya Sabha to meet on 27th April 1970.
	सं० आर० एस० 1/2/70-एल० दिनांक 9-4-70।	राज्य सभा सचिवालय	राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा को 27 अप्रैल 1970 को आमंत्रित करना।
63	No. 53-ITC(PN)/70, dt. 10-4-70.	Min. of Foreign Trade	Errata (*I*) to Red Book Vol. II for the year April/70—March/71—Amendment No. 1.
64	No. 54-ITC(PN) /70, dt. 10-4-70.	Do.	Provisions for Public Notice No. 72-ITC (PN)/69, dt. 19th May 1969 will apply for the year 1970-71 with the amendment mentioned therein.
65	No. 55-ITC(PN)/70, dt. 12-4-70.	Do.	Grant of import licences for raw materials and components to actual users in the small scale sector during April/70 –March/71 items licensable on restricted basis.
66	No. 56-ITC(PN)/70, dt. 14-4-70.	Do.	Import of raw materials, components and spares by actual users in the small scale sector during April 70—March/71—Modes of Financing.
67	No. 57-ITC(PN)/ dt. 16-4-70.	Do.	Import Policy for Registered Exports for the period April/70—March/71 (Amendment No. 2).
	No. 58-ITC(PN)/70, dt. 16-4-70.	Do.	Export effort by units engaged in priority or other industries during the year 1969—Production of evidence regarding.
68	No. 4-ETC(PN)/70, dt. 20-4-70.	Do.	Export of 'double drawn' human hair and 'unkns' subject to floor prices.
69	No. 59-ITC(PN)/70, dt. 21-4-70.	Do.	Issue of import licences for raw materials to the D.G.T.D. units engaged in cable and wire Industry during April/70—March/71 period.
70	No. 3(1)/69-P&P dt. 22-4-70.	Do.	Reconstitution of the Board of Trade.
	सं० 3 (1) /69-पी० एण्ड पी० दिनांक 22 अप्रैल 1970	विदेशी व्यापार मंत्रालय	व्यापार बोर्ड को पुनर्गठित करना।
71	No. 60-ITC(PN)/70, dt. 22-4-70.	Min. of Foreign Trade	Import of raw materials, components and spares by new units in the small scale sector during April 1970—March 1971—basis of licensing.
72	No. 61-ITC(PN)/70, dt. 23-4-70.	Do.	The scheme of sale and distribution through Allotment releases from N.M.D.C. stock of rough precious stone procured from Burma auction.
73	No. 62-ITC(PN)/70, dt. 23-4-70.	Do.	Import Policy for the year April 1970—March 1971.
	No. 63-ITC(PN)/70, dt. 23-4-70.	Do.	Import of Drugs and Medicines (S. No. 87, 109/IV), during April 1969—March/70 period.
74	No. F. 7(25)/E. III (A)/ 69, dt. 25-4-70.	Min. of Finance.	Setting up of a Pay Commission.
	सं० एफ० 7 (25)-ई०-III(ए)/69, दिनांक 25-4-70।	वित्त मंत्रालय	एक वेतन आयोग की नियुक्ति करना।
75	No. 64-ITC(PN)/70, dt. 28-4-70.	Min. of Foreign Trade.	Export to Afghanistan under Indo-Afghan Trade Arrangements 1969-70.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	503
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	607
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	43
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	643
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	1785
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं ..	2313
भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	311
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	605
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	209
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	93
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	337
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	89
पूरक संख्या 22—	
23 मई 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	903
2 मई 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	913

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	503
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	607
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	43
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	643
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including Orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1785
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2313
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	311
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	605
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	209
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	93
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	337
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	89
SUPPLEMENT NO. 22	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 23rd May 1970	903
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 2nd May 1970	913

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ।

Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other then the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.

मंत्रिमंडल सचिवालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1970

सं० वी०-11012/1/70-तकनीकी—सांख्यिकी विभाग अधिसूचना सं० वी० 11012/1/70-तकनीकी दिनांक 25 मार्च तथा 20 अप्रैल, 1970 में निहित आदेशों में आंशिक रूपान्तरण करते हुए निम्नलिखित और अधिक परिवर्तन किए जाते हैं :—

(1) क्रमांक 6 के नीचे जोड़िए :—

7.निदेशक,
आंकड़ा एवं अर्थशास्त्र कार्यालय,
उड़ीसा सरकार,
भुवनेश्वर ।

(2) क्रमांक 7 के आगे 8 से 13 के रूप में दुबारा नम्बर लगाइए ।

के० पी० गीताकृष्णन, उप-सचिव

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(पैट्रोलियम तथा रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1970

सं० 55(17)/69-फर्टी-2—पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (पैट्रोलियम तथा रसायन विभाग) के संकल्प सं० 55(17)/69-फर्टी-2 दिनांक 2 जनवरी, 1970 का संशोधन करते हुए, कण्डिका (पैराग्राफ) 5 के स्थान पर निम्न कण्डिका प्रतिस्थापित की जाए :—

"5 आयोग अपनी रिपोर्ट 13 महीनों की अवधि के अन्दर पेश करेगा ।"

आदेश

आदेश दिया गया है कि संकल्प भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सारे मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए ।

एम० रामाकृष्णय्या, संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1970

सं० 1-15/68-जी०ओ०पी० (पूरक सूची सं० 23)—इस विभाग की 6-3-1970 की अधिसूचना सं० 1-15/68-जी०ओ० पी० (पूरक सूची सं० 22) के क्रम में निम्नलिखित थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार को सहकारी समितियों की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है । यह अनुसूची दिनांक 27-5-66 की अधिसूचना सं० 1-25/65-सी० सी०, जिसमें थोक उपभोक्ता सहकारी समितियों की गारंटी योजना दी गई है, के साथ प्रकाशित की गई थी ।

"दी पोरबन्दर सेन्ट्रल कन्जूमर्स कोआपरेटिव सोसायटी लि०, पोरबन्दर (गुजरात) ।"

एम० सत्यभामा, उप-सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 1970

सं० एफ० 22-1/69—सी० ए०/(2)—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 22/1/69 सी० ए०/(2), दिनांक 21 जनवरी 1970, के क्रम में डा० जी० एस० छाबड़ा, रीडर एवं अध्यक्ष, इतिहास विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू तवी, को भारत सरकार के संकल्प सं० 6/25/63/ए०-10 (सी० 5), दिनांक 20 नवम्बर 1965, के पैरा 3.1. ए०(6) के अनुसार, 3 अप्रैल 1971 को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिए भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के एक सामान्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

दिनांक 20 अप्रैल 1970

सं० एफ० 22/1/69 सी० ए०/(2)—भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 20 नवम्बर 1965 के संकल्प सं० 6/25/63 ए० 10(सी० 5) के पैरा 3.1. बी० के अनुसार डा० एन० के० सिन्हा, निवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष इतिहास विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय, 85-ए, एकडालिया रोड, कलकत्ता-19 को भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के संवादी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है । फिलहाल उनकी नियुक्ति की अवधि 3-4-1971 तक होगी ।

ए० एस० तलवार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1970

सं० एफ० 1-2/70 प्लानिंग-3—श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई को लोक सभा ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के सदस्य के रूप में 31 मार्च, 1973 तक काम करने के लिए चुना है ।

प्रो० सईद नुरूल हसन को राज्य सभा ने श्री एम० के० वैश्मपायन के स्थान पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के सदस्य के रूप में 31 मार्च, 1973 तक काम करने के लिए चुना है ।

भारत सरकार ने श्री अनिल मोहन गुप्त के स्थान पर प्रो० एस० वी० सी० अइया को केन्द्रीय सलाहकार मंडल के सदस्य के रूप मे 31 मार्च, 1973 तक काम करने के लिए नामित किया है ।

कुमारी सितीमौन सांवेन को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के सदस्य के रूप मे 31 मार्च, 1973 तक पुनः नामित किया गया है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उप-महानिदेशक (शिक्षा) डा० ओ० पी० गौतम को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल पर 31 मार्च 1973 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में पुनः नामित किया गया है ।

डा० ए० डी० जोसफ, एम० डी०, उप-निदेशक (शिक्षा), गुजरात को डा० के० एल० कामलीवाल के स्थान पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल पर 31 मार्च, 1971 तक भारतीय औषध परिषद के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है ।

जे० पी० नाईक
सलाहकार
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 1970

संकल्प

सं० वि० आ० पाच 502(37)/68—ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ों से असम में जो तबाही हुई है, वह केन्द्रीय सरकार व असम सरकार दोनों के लिए काफी चिंता का विषय रही है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ों से बार-बार होने वाली तबाही से असम के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए, यह आवश्यक है कि इस राज्य की बाढ़, भूरक्षण एवं जल-निकास-रोध समस्याओं का सामना करने के लिए एक समेकित योजना तैयार की जाए और उसे शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए । इस कार्य में भारत सरकार का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए विस्तृत और समेकित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के काम में तुरंत और प्रभावकारी कार्यवाही करने के लिये, भारत सरकार ने असम की राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है ।

2. बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :

1. केंद्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री	अध्यक्ष
2. बाढ़ नियंत्रण मंत्री, असम	सदस्य
3. वित्त मंत्री, असम	सदस्य
4. राजस्व मंत्री, असम	सदस्य
5. वन मंत्री, असम	सदस्य
6. बिजली मंत्री, असम	सदस्य
7. जनजाति क्षेत्र व भू-संरक्षण मंत्री, असम	सदस्य
8. सलाहकार, नेफा	सदस्य
9. अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग	सदस्य

3. इस बोर्ड को एक पूर्णकालिक सचिव की सहायता मिलेगी जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा असम सरकार के साथ सलाह करके की जाएगी । बोर्ड का मुख्यालय गौहाटी में होगा ।

4. यह बोर्ड एक उच्चाधिकार-संपन्न नीति-निर्धारक संस्था होगी और यह विभिन्न बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के कार्यान्वयन में प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा । यह बोर्ड प्रक्कलनों का अनुमोदन करके धन राशियों के आवटनों को स्वीकृति प्रदान करेगा ।

5. यह बोर्ड अपने कार्य नियम स्वयं बनाएगा ।

6. घाटी के बाढ़ नियंत्रण की एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए और कार्यों का कार्यान्वयन करने के लिए असम सरकार पूर्ण कालिक संस्था, नामतः ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग स्थापित करेगा । ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पदेन सदस्य होगा ।

7. आयोग के कार्य का पुनरवलोकन करने के लिए और बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के आयोजन, डिज़ाइन और कार्यान्वयन के दौरान उठने वाली समस्याओं पर सलाह देने के लिए असम सरकार एक तकनीकी सलाहकार बोर्ड स्थापित करेगी । ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष इस बोर्ड के अध्यक्ष का नामन करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राज्य सरकार/भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/प्रधान मंत्री के सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी व सैनिक सचिव/भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक/योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि वह इसे राज्य के राजपत्र में सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित कर दे ।

वी० एस० बंसल, संयुक्त सचिव

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम तथा रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1970

सं० डब्ल्यू० ई० 48/7/70—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3(ए०) के अनुसार भारत सरकार एतद्द्वारा श्री आई० एन० साही, अपर सचिव, श्रम रोजगार व पुनर्वास मंत्रालय को डा० एम० टी० मिरानी, सह सचिव, श्रम, रोजगार व पुनर्वास मंत्रालय के स्थान पर 5 मई, 1970 से उक्त शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

2. तदनुसार भारत सरकार के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 के 20 दिसम्बर, 1958 अग्रहायण 29, 1880 में प्रकाशित श्रम व रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० ई० एण्ड पी० 4(24)/58, दिनांक 12 दिसम्बर 1958 (समय-समय पर संशोधित) की प्रविष्टि में निम्नलिखित निर्दिष्ट परिवर्तन किये जायें :—

1—डा० एस० टी० मिरानी, सह सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली ।	भारत सरकार द्वारा नामित

के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाये :—

1—श्री आई० डी० एन० साही, अपर सचिव, श्रम, रोजगार व पुनर्वास मंत्रालय, नई दिल्ली ।	भारत सरकार द्वारा नामित

हंस राज छाबड़ा, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Statistics)

New Delhi, the 27th April 1970

No. 11/4/68-*Tech.*—In continuation of this Department Notification No. 8/7/66-Estt.II, dated the 5th December. 1966, the following have been nominated as members of the Standing Committee for Improvement of Industrial Statistics :—

1. Shri V. V. Divatia, Adviser (Statistics), Department of Statistics, Reserve Bank of India, Bombay.
2. Shri K. L. Saxsena, Joint Director, Central Statistical Organisation, *vice* Dr. S. G. Tiwari.
3. Economic and Statistical Adviser, Government of Haryana, Chandigarh for a period of one year with effect from 5th December 1969 *vice* Director, Economic, Intelligence and Statistics, Uttar Pradesh, Lucknow.

The 5th May 1970

No. V-11012/1/70-*Tech.*—In partial modification of orders contained in the Department of Statistics Notification No. V-11012/1/70-Tech., dated the 25th March and the 20th April, 1970, the following further changes are made.—

(1) Below S. No. 6 add—

7. Director, Bureau of Statistics and Economics, Government of Orissa, Bhubaneswar.

(2) Renumber S. No. 7 onwards as 8 to 13.

K. P. GEETHAKRISHNAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS & MINES & METALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 11th May 1970

RESOLUTION

No. 1(78)/69-*PPD.*—The Government of India have considered the Report of the Oil Prices Committee (hereinafter referred to as OPC) set up on the 14th June, 1968 under the chairmanship of Shri Shantilal H. Shah, M.P. to advise on the manner of determining ex-refinery and landed prices of petroleum products in the future and on other connected matters.

2.1. After a careful study of the recommendations made, and keeping in view that the country still imports 60% of its total crude oil requirements, Government have decided to accept the OPC's recommendation relating to the continuance of the concept of import parity in the initial build-up of the prices of bulk refined petroleum products ex-refineries/ports.

2.2. The Committee has expressed the view that the introduction of uniform prices throughout the country is not feasible and has also advised against a regional pool. This recommendation is accepted.

2.3. (a) The Government have taken into account the fact that posted f.o.b. prices of certain pertoleum products ex-Bandar Mah-Shahr had registered a drop on 27-3-69, which was a consequence of the down-ward trend in the net f.o.b. prices of crude oil in West Asia, resulting ultimately in a reduction of 10 cents per barrel cost of crude from $ 1.38 to $ 1.28 per barrel already enforced by Government. In the context of this fact, the ex-refinery prices of bulk refined products and Bitumen grades in the case of all refineries in the country and landed prices of imported products, where applicable, will be determined on the basis of import parity, calculated as follows :

(i) F.O.B. of all bulk products, excluding Bitumens, will be the lowest of Platt's posted F.O.B. price, ex-Bandar Mah-Shahr as on 26-3-69, with a discount of 4% applied thereon;

(ii) Marine freight will be calculated at General Purpose vessel rates applicable for June, 1969 for all products except Bitumens;

(iii) For Bitumens, the derived F.O.B. price, as on 18-5-65 ex-Abadan, with an appropriate increase to provide for neutralising the effect of devaluation of pound sterling in November, 1967, will be deemed to be the posted F.O.B. price. To this, 4% discount will be applied, to arrive at the net F.O.B. price. The marine freight will be at the rate applicable to Medium Range vessels in June, 1969 with the premium recommended by the O.P.C.

(iv) Future variations in the net F.O.B. prices, referred to above, will not be allowed unless specifically authorised by Government for good and valid reasons referred to in the succeeding para.

(v) Keeping in view the fact that what is actually being imported in the country, currently, is crude oil and not petroleum products (with minor exceptions), the variations in Marine freight and wharfage on imports of crude oil, which is actually used in manufacturing bulk refined products (including naphtha) and bitumen grades, will be reflected in the product prices through the C&F Adjustment Account. While doing so, the actual capacity of the relevant port to receive crude oil tankers will be kept in view. In the case of oil companies using indigenous crude, the variations will be admissible on a notional basis. However, in the case of actual imports, if any, of petroleum products, such variations will be allowed to be recovered to the extent of actuals through an appropriate mechanism.

(b) The recommendation of the O.P.C. that future reductions in the prices of Middle East crude oil should be reflected in the shape of further discounts on posted f.o.b. prices of products, is accepted in principle; the Government, however, reserve the right to deal with the situation as it arises depending on the conditions obtaining at that time.

(c) The OPC has recommended that consequent on the inland refineries becoming additional pricing points for bulk refined products (including Naphtha) and Bitumen grades and the resultant revision of the supply areas, under-recoveries of freight resulting from out-of-zone movements as well as coastal movements, should be re-imbursed to the oil companies on the basis of actuals through the levy of a surcharge on an all-India basis. The Government accept this recommendation. The surcharge, which may be altered if necessary on the basis of actual experience, will be levied on all bulk refined products (excluding aviation gasolenes of all grades, Bitumen grades, lubricants and greases). The under-recoveries on all bulk refined petroleum products (excluding Bitumen grades lubricants and greases) are reimbursible. The rates of surcharge and the detailed mechanism of re-imbursement will be worked out by Government and intimated to the oil companies separately. A separate account will be maintained for collection of surcharge on Naphtha and the related under-recoveries.

2.4. The recommendation of the OPC for treating all inland refineries as pricing points in addition to the main ports is accepted.

2.5. Government accept the recommendations of the Committee on marketing and distribution charges, and on profit margins.

Notwithstanding the foregoing,

(i) the basic ceiling selling prices of aviation gasolenes of all grades and ATF, which are notified by Government from time to time, will continue to remain at the same level as on 1-5-70 except for variations which may be authorised by the Government. The consequent under-realisation in respect of ATF will be compensated with effect from 1-6-1970 through suitable adjustment of the price of Furnace Oil;

(ii) the pricing of Naphtha used for the manufacture of approved products, such as fertiliser, will be on the lines suggested by the O.P.C.

2.6. (a) The existing system of "Block Control" on marketing and distribution charges and profit of the oil marketing companies in respect of lubricants and greases will be continued, for the present, at the ceiling rates recommended by the OPC. This is, however, subject to the condition that the prices of lubricants and greases will not be increased from the existing levels (*i.e.* as on the first day of May, 1970) without the specific approval of Government. However, on the method of control of furnished lubricants as well as lube base stocks, Government will take a final view on receipt of the supplemental report which the OPC will give on the subject. The Government accept the recommendation of the OPC to exclude Specialities from the purview of Block Control on marketing/distribution charges and profit, the details of which will be intimated to the oil companies separately. The Committee has not proposed any ceiling selling prices for Specialities like Carbon Black Feed Stock, Iomex, L.S.H.S. etc. Government accept this recommendation which will be applied to R.F.O. as well. However, Tea Drier Oil will be excluded from the list of Specialities and its price will be equated to that of Furnace Oil.

2.6. (b) The basic ceiling selling prices of all bulk refined petroleum products, Bitumens and Naphtha (but excluding aviation gasolenes), will be re-calculated for each port in the manner suggested by the OPC and as modified by Government. The Government have decided that the basic ceiling selling prices of Motor Spirit 93 Octane No. and Furnace Oil should be increased suitably in accordance with the recommendations of the O.P.C. as modified by Government.

2.7. In the case of High Speed Diesel Oil, Government are unable to accept the recommendation of the O.P.C. for increasing the rate of dealers' commission. The dealers' commission on Motor Spirit and Kerosene will continue at the existing rates as recommended by the Committee.

3. Government accept the recommendation of the O.P.C. that the concept of Free Delivery Zone currently applicable to Motor Spirit and H.S.D. Oil should be extended to Furnace Oil also.

4. The decisions herein contained about the prices of petroleum products will come into force with effect from 1st June, 1970 so as to afford adequate time for making the calculations of the revised selling prices throughout the country on the new basis enunciated above, and will remain in force initially for a period of 3 years from that date, but will be subject to the adjustments recommended by the Committee. Government may, however, extend their validity for a further period or periods at its discretion.

5. In regard to some of the other recommendations of the Committee, the decisions of Government will be announced in due course.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

E. N. MANGAT RAI, Special Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 11th May 1970

No. 55(17)/69-Ferts.II.—In modification of the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Petroleum and Chemicals) Resolution No. 55(17)-Ferts. II, dated 2nd January, 1970, for paragraph 5, the following shall be *substituted* :—

"The Commission will submit its report within a period of thirteen months."

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India.

M. RAMAKRISHNAYYA, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Co-operation)

New Delhi, the 14th May 1970

No. 1-15/68-GOP (Suppl. List No. 23).—In continuation of this Department Notification No. 1-15/68-GOP (Suppl. List No. 22), dated 6-3-1970, the following Wholesale Consumers Cooperative Store is added to the Schedule of Cooperative Societies published alongwith the Notification No. 1-25/65-CC, dated 27-5-66, containing the Guarantee Scheme for Wholesale Consumers Cooperatives :—

"The Porbandar Central Consumers' Cooperative Society Ltd., Porbandar (Gujarat)."

S. SATYABHAMA, Dy. Secy. (CP)

MINISTRY OF EDUCATION & YOUTH SERVICES

New Delhi, the 13th April 1970

No. F. 22/1/69-CAI-2.—In continuation of this Ministry Notification No. F. 22/1/69-CAI(2), dated the 21st January, 1970, Dr. G. S. Chabbra, Reader and Head, Department of History, University of Jammu, Jammu Tawi, is appointed as an ordinary Member of the Indian Historical Records Commission in accordance with para 3.I.A(6) of Government of India Resolution No. 6/25/63-A.10(C.5), dated the 20th November, 1965 for an unexpired portion of the term expiring on the 3rd April, 1971.

The 20th April 1970

No. F. 22/1/69-CAI-2.—In accordance with Para 3.1.B. of the Government of India, Ministry of Education Resolution No. 6/25/63-A.10(C.5), dated the 20th November, 1965, Dr. N. K. Sinha, Retired Professor and Head of Department of History, Calcutta University, 85-A-Ekdalia Road, Calcutta-19 is appointed as corresponding Member of the Indian Historical Records Commission. The term of his appointment will for the present be up to 3rd April, 1971.

A. S. TALWAR, Under Secy.

New Delhi, the 30th April 1970

No. F. 1-2/70-Plg.III.—Smt. Sangam Laxmi Bai has been elected by the Lok Sabha to serve as a member of the Central Advisory Board of Education up to 31st March, 1973.

Prof. Saiyid Nurul Hasan has been elected by the Rajya Sabha to serve as a member of the Central Advisory Board of Education up to 31st March, 1973 *vice* Shri S. K. Vaishampayen.

The Government of India has nominated Prof. S. V. C. Aiya as a member of the Central Advisory Board of Education up to 31st March, 1973 *vice* Shri Anil Mohan Gupta.

Miss Sitimon Sawain has been renominated as a member of the Central Advisory Board of Education up to 31st March, 1973.

Dr. O. P. Gautam, Deputy Director General (Education), Indian Council of Agricultural Research has been renominated as a representative of the Indian Council of Agricultural Research on the Central Advisory Board of Education up to 31st March, 1973.

Dr. A. D. Joseph, M.D., Deputy Director (Education), Gujarat has been nominated as a representative of the Indian Medical Council on the Central Advisory Board of Education up to 31st March, 1971 *vice* Dr. K. L. Kasliwal.

J. P. NAIK, Adviser

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER.

New Delhi, the 13th May 1970

RESOLUTION

No. DW.V.502(37)/68.—The ravages caused in Assam by the floods in the Brahmaputra have been a matter of considerable concern to the Central Government as well as the Government of Assam. In order to ensure a reasonable amount of protection to the people of Assam from the recurrent damage by the floods in Brahmaputra, it is necessary that an integrated plan to tackle the flood, erosion and drainage congestion problems of the State is prepared and implemented speedily. In order to ensure the close cooperation of Government of India in this task and to facilitate prompt and effective action in the formulation and implementation of a comprehensive and coordinated plan for flood control, the Government of India have, in consultation with the State Government of Assam, decided to set up the Brahmaputra Flood Control Board.

2. The Board will consist of the following :

Chairman

1. Union Minister of Irrigation & Power.

Members

2. Minister of Flood Control, Assam.
3. Minister of Finance, Assam.
4. Minister of Revenue, Assam.
5. Minister of Forests, Assam.
6. Minister of Power, Assam.
7. Minister of Tribal areas and Soil Conservation, Assam.
8. Adviser, NEFA.
9. Chairman of the Brahmaputra Flood Control Commission.

3. The Board will be assisted by a whole-time Secretary to be appointed by the Government of India in consultation with the Government of Assam. The headquarters of the Board will be situated at Gauhati.

4. The Board will be a high powered policy making body and will decide priorities in the implementation of the various flood control schemes. The Board will accord sanction to estmiates and approve the allocation of funds.

5. The Board will frame its own rules of business.

6. For preparing a comprehensive plan of the flood control of the valley and for execution of works the Assam Government will set up a whole-time organisation *viz.*, Brahmaputra Flood Control Commission. The Chairman of the Brahmaputra Flood Control Commission. The Chairman of the Brahmaputra Flood Control Commission will be an *ex-officio* Member of the Brahmaputra Flood Control Board.

7. The Government of Assam will also set up a Board of Technical Consultants to review the work of the Commission and to advise on the problems that may arise during planning, design and execution of flood control schemes. The Chairman of this Board will be nominated by the Chairman of the Brahmaputra Flood Control Board.

ORDER

ORDERED that a c py of the Resolution be communicated to the State Government/All Ministries of Government of India/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government be requested to publish it in the State Gazette for general information.

B. S. BANSAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 15th May 1970

No. W.E. 48/7/70.—In pursuance of Rule 3(a) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby nominates Shri I. D. N. Sahi, Additional Secretary, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation as Chairman of the said Board with effect from the 5th May, 1970, *vice* Dr. S. T. Merani, Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment.

2. The following changes shall accordingly be made in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P 4(24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part I, Section 1 dated December, 20, 1958/ Agrhayana 29, 1880, as amended from time to time :—

For the existing entry *viz.*

"Dr. S. T. Merani, Joint Secretary, Ministry of Labour, Employment New Delhi.—Nominated by the Government of India.

the following shall be *substituted* :—

"Shri I. D. N. Sahi, Additional Secretary, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, New Delhi.—Nominated by the Government of India."

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970